हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस०जे०-ए०-बी(1)6 / 2012

तारीख शिमला—2,

29 जुलाई, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रधानाचार्य वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रधानाचार्य वर्ग—1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृश्ठांकन संख्याः यथोपरि। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः— तारीख शिमला—2

29 जुलाई, 2016

- 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(वित्त/विधि/कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
- 2. निदेशक, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश शिमला –09
- 3 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5
- 4 गार्ड फाईल।

हस्ता / — उप सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन, विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान (आई०सी०एस०ए०), सुन्दरनगर में प्रधानाचार्य, वर्ग—। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्निति नियम।

1. पद का नामः प्रधानाचार्य

2. पद (पदों की संख्या)ः 01 (एक)

वर्गीकरणः वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमानः i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः

15600-39100 / - रूपए + 6600 / - रूपए ग्रेड पे।

ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:

स्तम्भ 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200 / —रूपए प्रतिमास ।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः 45 वर्ष और इससे कम ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सिहत पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पिल्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पिल्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पिल्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि <u>पद(पदों)</u> को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

अनिवार्य अर्हता (एं) :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में शिक्षा स्नातक (बी० एड०) ।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक (बी० एड०) सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक (बी० एड०) सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में शिक्षा का डिप्लोमा।

या

दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स।

- (iii) अन्धों और श्रवण बाधितों के लिए किसी संस्थान में आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव।
- (iv) अभ्यर्थी आर०सी० आई० के पास अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

वॉछनीय अर्हता(एं) :

- (i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) या (श्रवण बाधिता) में एम० एड० ।
 - (ii) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)की दशा में लागू होंगी या नहीं :

लागू नहीं । आयुः शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:
- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा के आधार पर, धारणाधिकार (टेन्यूॲर) आधार पर, सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति. सैंकेण्डमैंट. स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतताः

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्नति, / जिनसे सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः

लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः

लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथारिथति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य, वर्ग—I (राजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियांः</u>

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्य, को 22200 / — रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 666 / — रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) <u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी</u>

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV)<u>चयन प्रक्रियाः</u>

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। (VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200 / रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666 / रूपए की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से रकम की वृद्धि के लिए हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उस सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0 आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदा)ं की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

16. आरक्षणः

17. विभागीय परीक्षाः

18. शिथिल करने की शक्ति:

प्रधानाचार्य, वर्ग—I (राजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रधानाचार्य, वर्ग—I (राजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रधानाचार्य, वर्ग—I (राजपत्रित) के रूप में से प्रारम्भ होने और.... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अविध के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिश्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्शानुवर्श आधार पर <u>विस्तारण नवीकरण</u> के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्श के दौरान संतोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200/- रूपए प्रतिमास होगी।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेश अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेश अवकाश एक कलैण्डर वर्श तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्श के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (इयूटी) से अनिधकृत अनुपिश्यित से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (इयूटी) से अनिधकृत अनुपिश्यित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (इयूटी) से अनुपिश्यित की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्श का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ इ०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में: 1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता) 2	
नाम व पूरा पता	

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-6 /2012, dated: 29th July, 2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-A-B(1)-6/2012

dated: Shimla-02 the

29th July, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Principal, Class-I (Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Principal, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2016.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst No. as above, dated: Shimla-02

29th July, 2016

Copy to:-

- The A.C.S./Pr. Secretaries/Secretaries (Finance/Law/Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
- The Director, SCs, OBCs and Minorities Affairs, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09. He is requested to procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
- 3 The Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-05 for publication into the Govt. Gazette.
- 4 Guard File.

-Sd/-

Deputy Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

DRAFT RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINCIPAL, CLASS-I (GAZETTED), IN THE INSTITUTE FOR CHILDREN WITH SPECIAL ABILITITES (ICSA), SUNDERNAGAR, UNDER THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Principal	
2.	Number of post(s)	01 (One)	
3.	Classification	Class-I (Gazetted).	
4.	(i) Scale of Pay	i) Pay scale for regular incumbent:- Pay Band ₹ 15600-39100 + ₹6600/- Grade Pay.	
		ii) Emoluments for contract employee:- Rs. 22,200/- as per details given in Col. No. 15-A.	
5.	Whether Selection post or non-selection.	Not applicable	
6.	Age of direct recruitment	Between 18 and 45 years.	

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

- 1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchanges, as the case may be.
- 2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum educational and other qualification required for direct recruit(s).	(a) (i)	ESSENTIAL QUALIFACTION(S):- A second class Master Degree from a
			recognized University.
		(ii)	B.Ed. Special Education (VI) or (HI)
			Or
			-Post Graduate Professional Diploma in Special Education (VI) or (HI) with B.Ed. in General Education,
			Or
			-Diploma in Special Education (VI) or (HI)/Diploma in Education in Special Education (VI) or (HI) with B. Ed in General Education
			Or
			- Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment or Hearing Impaired.
			Eight years teaching experience in an Institute for the Blind or Hearing Impaired.
		(iv)	The candidate must be registered with RCI.
		<u>(b)</u>	DESIRABLE QUALIFICATION:-
		<u>(i)</u>	M. Ed. in Special Education (VI) or (HI).
		(ii)	Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions.
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for	A	ge: Not applicable
	qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).		ducational Qualification: Not applicable
9.	Period of probation, if any	a)	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
		b)	No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	0	00% by direct recruitment on regular basis r by recruitment on contract basis, as the ase may be.

11.	In case recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.	Not applicable			
12.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition?	Not applicable			
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.			
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.			
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.			
15-A	Selection for appointment to the post by Contract appointment.	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-			
		(I) CONCEPT:			
		(a) Under this policy the Principal, Class-I (Gazetted), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.			
		Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.			
		(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC: The ACS/Pr. Secy./Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission. (c) The selection will be made in accordance			
		with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.			

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.

The Principal, Class-I (Gazetted) appointed on contract basis will be paid contractual amount @ ₹ 22,200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The A.C.S./Pr. Secretary/Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 22,200/-P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 666/-(3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/ selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d)Unauthorized absence from duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

		(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
		(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, CPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as perscribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18.	Powers to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Form of	Contract	/agreement	to be	executed	between	the	Principal,	Class-I,	(Gazetted)	and the
Governn	nent of Hin	nachal Prade	esh, thro	ough the	A.C.S./Pr. S	ecreta	ıry/Secreta	ry (SJ&E)	to the Govt	of H.P :-
This agre	eement is	made on thi	S		day	of		in	the year	
between.	. Sh./Smt.			S/O/I	D/O Sh			R/O		
				Conti	ract appoi	ntee ((here in a	fter calle	d the(FIRS'	T PARTY)
AND The	e Governo	of Himach	ıal Prad	esh throug	the A.C.	S./Pr.	Secretary/S	Secretary	(SJ&E) to th	ie Govt. o
H.P (here	e –in –after	the SECON	D PART	Υ).						

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Principal, Class-I, (Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.22,200/- per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.
- 4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee.

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence for the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6 An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
- The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and

year first, above written	
IN THE PRESENCE OF WITNESS.	
1	
(SIGNATURE OF FIRST PARTY)	(Name and full address)
2.	
(Name and full address)	
IN THE PRESENCE OF WITNESS	
1	
(Name and full address)	
(Signature of SECOND PARTY)	
2	
	(Name and full address)